झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 6664/2016

मैसर्स श्री सनीजी स्टील एंड पावर लिमिटेड ग्राम - घनश्यामपुर, डाक घर नित्यनंदपुर, थाना - गंगाजलघाटी, जिला- बांकुरा-722177 (पश्चिम बंगाल) में स्थित है और "सेंटर प्वाइंट", 21, हेमंत बसु सरणी, 5 वीं मंजिल, कमरा नंबर 508, कोलकाता -700001 में पंजीकृत कार्यालय, इसके हस्ताक्षरकर्ता सदस्य श्री संदीप खंडेलवाल, मैसर्स श्री सैनीजी स्टील एंड पावर लिमिटेड के खरीद प्रबंधक केंद्र बिंदु के माध्यम से, हेमंत बसु सरणी, 5वीं मंजिल कमरा नंबर 508, कोलकाता -700001।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने सचिव औद्योगिक विभाग, झारखंड सरकार, डाक घर + थाना - डोरंडा, जिला रांची, रांची के माध्यम से; झारखंड

2. उप निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय झारखंड, रांची, डाक घर + थाना - डोरंडा, जिला रांची, झारखंड

3. अध्यक्ष, झारखंड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद, तीसरी मंजिल नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची;

4. मेसर्स शालिग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अपने निदेशक श्री रूपक पसारी के माध्यम से कोर्ट रोड, चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम में अपना पंजीकृत कार्यालय है और इकाई बाराबंधुआ, प्लॉट नंबर 561/562, पोका, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है; ... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अनुज बर्मन, एडवोकेट
श्री अनूप कुमार अग्रवाल, एडवोकेट श्री ए. के. अग्रवाल, एडवोकेट

उत्तरदाता राज्य के लिए : श्री संजय कुमार तिवारी, एससी

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा केस नंबर 2 में पारित ज्ञापन संख्या 523 दिनांक 15.02.2016 में निहित पुरस्कार/डिक्री को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। जेएचएमएसईएफसी 01/2015 के तहत जिसके तहत याचिकाकर्ता को 14,82,917/- रुपये की बकाया मूल राशि के लिए 14,82,917/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17.05.2013 से अधिसूचित बैंक ब्याज दर के तीन गुना के साथ है, जब तक कि अंतिम भुगतान वास्तव में नहीं किया जाता है।

.3. मामले का निर्विवाद तथ्य यह है कि उत्तरदाता संख्या 4 को 16.07.2014 को एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इससे पहले, दिनांक 27042013 के क्रय आदेश के विरुद्ध दिनांक 30092014 तक परिकलित 14,82,91522 रुपए की मूल राशि और 14,83,88265 रुपए के ब्याज का बकाया दावा था। झारखंड सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद ने 05.02.2015 को मामला स्वीकार किया। नोटिस पर, रिट याचिकाकर्ता, जो विपरीत पक्ष था, उक्त सुविधा परिषद के उत्तरदाता संख्या 3 के सामने, अपनी लिखित आपत्ति दायर की। लिखित आपत्ति में रिट याचिकाकर्ता ने कार्यवाही की संधार्यता पर विरोध किया किन्तु इसे खारिच करते हुए,सात सदस्य उक्त सुविधा परिषद के सदस्यों ने विपरीत पक्षकार को, जो यहां रिट याचिकाकर्ता है, उक्त भुगतान करने का निर्देश दिया, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड बनाम महाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) और एक अन्य **(2023) 6 एससीसी 401**, पर भरोसा करते है, जिसका पैराग्राफ-50 और 51 निम्नानुसार पढ़ा जाता है : -

"50. इस मोड़ पर, इस मुद्दे पर सिल्पी इंडस्ट्रीज मामले [सिल्पी इंडस्ट्रीज बनाम केरल एसआरटीसी, (2021) 18 एससीसी 790: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 439] में इस न्यायालय द्वारा की गई बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणियों को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता है: (एससीसी पैरा 42-44)

"42. ... हमारे विचार में, एमएसएमईडी अधिनियम के तहत प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिए, विक्रेता को अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख को अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होना चाहिए। किसी भी स्थिति में, एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के तहत इकाई के पंजीकरण से पहले किए गए अनुबंध के अनुसार आपूर्ति के लिए, ऐसी इकाई द्वारा कोई लाभ नहीं मांगा जा सकता है, जैसा कि एमएसएमईडी अधिनियम के तहत सोचा गया है।

43. लघु और सहायक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित भुगतान पर ब्याज के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अधिनियम, 1993, इस न्यायालय ने शांति कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम एसईबी [शांति कंडक्टर्स (पी) लिमिटेड बनाम असम एसईबी, (2019) 19 एससीसी 529: (2020) 4 एससीसी (सीआईवी) 409] के फैसले में माना है कि माल/सेवाओं की आपूर्ति की तारीख को प्रासंगिक तिथि के रूप में लिया जा सकता है, पूर्वोक्त अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए आपूर्ति के लिए अनुबंध दर्ज किए जाने की तारीख के विपरीत। उक्त अनुपात को भी लागू करने पर भी, अपीलकर्ता अधिनियम का लाभ लेने का हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत ज्ञापन दाखिल करने का सहारा लेकर, अनुबंध में प्रवेश करने और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के बाद, कोई भी एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत वर्गीकृत होने की कानूनी स्थिति को एक पूर्व प्रभावी के रूप में नहीं मान सकता है, जिस तारीख को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ अनुबंध में प्रवेश किया था।

44. अपीलकर्ता सूक्ष्म या लघु उद्यम या आपूर्तिकर्ता नहीं बन सकता है, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अर्थ के भीतर लाभ का दावा करने के लिए, अनुबंध में प्रवेश करने और माल और सेवाओं की आपूर्ति के बाद पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करके। यदि कोई पंजीकरण प्राप्त किया जाता है, तो वह भावी होगा और पंजीकरण के बाद वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लागू होगा लेकिन पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता है। प्रावधान की कोई अन्य व्याख्या बेतुकापन पैदा करेगी और कानून द्वारा अभिप्रेत पार्टी के पक्ष में अनुचित लाभ प्रदान करेगी।

51. उपर्युक्त अनुपात के बाद, यह माना जाता है कि एक पार्टी जो अनुबंध में प्रवेश करने की तारीख पर एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 2 (एन) के अनुसार "आपूर्तिकर्ता" नहीं थी, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में कोई लाभ नहीं ले सकती थी। कोई पक्ष एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत लाभ का दावा करने के लिए एक सूक्ष्म या लघु उद्यम या आपूर्तिकर्ता नहीं बन सकता है, जो अनुबंध में प्रवेश करने और माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के बाद पंजीकरण प्राप्त करने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत करता है। यदि कोई पंजीकरण बाद में प्राप्त किया जाता है, तो उसका प्रभाव भावी प्रभाव होगा और पंजीकरण के बाद माल की आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने के लिए लागू होगा। वही काम नहीं कर सकता

पूर्वव्यापी रूप से। तथापि, क्षेत्राधिकार का मुद्दा होने के कारण यदि ऐसा

मुद्दा उठाया जाता है तो इसका निर्णय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मध्यस्थ अधिकरण के रूप में कार्य करने वाली सुविधा परिषद/संस्थान/केन्द्र द्वारा भी किया जा सकता है। (महत्त्व सन्निविष्ट)

और प्रस्तुत करता है कि चूंकि उत्तरदाता संख्या 4 का पंजीकरण एमएसएमई के रूप में विवाद के बाद प्राप्त किया गया था, जिसके संबंध में प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा बकाया राशि का दावा किया गया है, इसलिए ऐसा दावा पूर्वव्यापी रूप से संचालित नहीं हो सकता है। इसलिए, उक्त विवाद का निर्णय सुविधा परिषद द्वारा नहीं किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अगले के फैसले पर भरोसा करते हैं

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड, बोकारो बनाम झारखंड राज्य के मामले में सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार, रांची और अन्य के माध्यम से **इस न्यायालय की** खण्ड पीठ ने डब्ल्यूपीसी संख्या 3699/2015 पैराग्राफ -24 से 26 में पारित किया, जिसमें से निम्नानुसार पढ़ें: -

24. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और अभिलेख का अध्ययन करने के बाद, हम पाते हैं कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 अपने शब्दों में स्पष्ट और सुस्पष्ट है, जब यह कहती है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद में कम से कम तीन नहीं बल्कि पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिन्हें उस धारा के तहत विस्तृत श्रेणियों में नियुक्त किया जाएगा। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार परिषद में और अधिक सदस्यों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2007 के नियमों का नियम 4 एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन था, जब इसमें परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था जिसमें परिषद में कम से कम पांच और नौ से अधिक सदस्य नहीं थे, और वास्तव में, उक्त नियम के अनुसरण में, परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा नौ सदस्यों के साथ भी किया गया था। स्पष्ट रूप से उक्त परिषद का गठन 2007 के नियमों के नियम 4 के अनुसार था, जबकि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 का स्पष्ट उल्लंघन था। यदि याचिकाकर्ता को आक्षेपित पंचाट को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अधिनिर्णय को चुनौती देने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वाणिज्यिक न्यायालय की ओर से आने वाला एकमात्र उत्तर यह है कि परिषद का गठन नियमों के अनुसार था, जो वाणिज्यिक न्यायालय के लिए बाध्यकारी था, और चूंकि वाणिज्यिक न्यायालय के लिए इस आधार पर अपील पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि तदनुसार, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के लिए कोई प्रभावी और प्रभावोत्पादक उपाय उपलब्ध नहीं था। वास्तव में कोई नहीं है

*25. **व्हर्लपूल कारपोरेशन के** मामले (सुप्रा) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों पर भरोसा किया है, जिसमें कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी*

लिमिटेड बनाम आईटीओ, कंपनीज डिस्ट्रिक्ट लिमिटेड, मैं, एआईआर 1961 एससी 372 में रिपोर्ट किया गया है, और निम्नानुसार आयोजित किया है: -

"19. कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड बनाम आईटीओ, कंपनी जिला कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड में एक और संविधान पीठ का निर्णय। मैंने निर्धारित किया: "हालांकि निषेध या उत्प्रेषण की रिट नहीं होगी

एक कार्यकारी प्राधिकारी के खिलाफ मुद्दा, उच्च न्यायालयों के पास एक उपयुक्त मामले में एक आदेश जारी करने की शक्ति है जो एक कार्यकारी प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करने से रोकता है। जहां क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करने वाले कार्यकारी प्राधिकारी की ऐसी कार्रवाई या किसी व्यक्ति को लंबी कार्यवाही और अनावश्यक उत्पीड़न के अधीन करने की संभावना है, उच्च न्यायालय ऐसे परिणामों को रोकने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिकार क्षेत्र के बिना काम करने वाले आयकर अधिकारी के खिलाफ उत्प्रेषण और निषेध की रिट जारी की जा सकती है।

20. तब से पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है, लेकिन इन निर्णयों पर कोई संक्षारक प्रभाव नहीं पड़ा है, जो पुराने होने के बावजूद, इस क्षेत्र को जारी रखते हैं कि कानून संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के रूप में, वैकल्पिक वैधानिक उपायों के बावजूद, प्रभावित नहीं होता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां जिस प्राधिकारी के खिलाफ रिट दायर की गई है, उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या बिना किसी कानूनी आधार के अधिकार क्षेत्र को हड़पने का इरादा था।

(महत्त्व सन्निविष्ट)।

26. इस विषय पर स्थापित कानून के मद्देनजर, हम पाते हैं कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील के विशिष्ट प्रावधान के बावजूद, ये रिट आवेदन काफी बनाए रखने योग्य हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित पुरस्कार/नोटिस को परिषद की योग्यता के आधार पर चुनौती दी गई है, जिसका गठन एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 के अधिकारातीत है। तथ्य यह है कि 2017 नियमों का नियम 4 एमएसएमईडी अधिनियम का अल्ट्रा-वायरस था, न केवल याचिकाकर्ता का तर्क है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा भी अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और 2007 के नियमों को निरस्त कर दिया है, जिससे 2017 के नए नियम लाए गए हैं।

उसमें नया नियम 4 लाया जा रहा है, जो एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 21 के अनुरूप है।

और प्रस्तुत करता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के

बावजूद, यह रिट याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य है कि आक्षेपित पुरस्कार को परिषद की योग्यता के आधार पर चुनौती दी गई है; जिसका संविधान *एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 21 के* अधिकारातीत है

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सूक्ष्म और सूक्ष्म

लघु उद्यम सुविधा परिषद में कम से कम तीन सदस्य नहीं बल्कि पांच से अधिक सदस्य नहीं होंगे बल्कि निर्विवाद रूप से पूर्ववर्ती 2007 नियमावली के नियम 4 के अनुसार सुविधा परिषद होगी जिसमें परिषद में कम से कम पांच और अधिक से अधिक नौ सदस्यों वाली सुविधा परिषद के गठन का प्रावधान है। इसमें सात सदस्य थे। इसलिए, सुविधा परिषद का गठन, जिसने आक्षेपित अधिनिर्णय/आदेश पारित किया, *अधिकारातीत था*

एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006. इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि पुरस्कार /

> उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा केस संख्या जेएच्ऍमएसईएफसी 01/2015 में पारित मेमो नंबर 523 दिनांक 15.02.2016 में निहित है। जिसमें याचिकाकर्ता को 17.05.2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक ब्याज दर के तीन गुना के साथ 14,82,917/- रुपये की बकाया मूल राशि के लिए 14,82,917/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, जब तक कि वास्तव में अंतिम भुगतान नहीं किया जाता है, रद्द और ख़ारिज कर दिया जाये

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को रद्द करने और उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा मामला संख्या जेएचएमएसईएफसी 01 में पारित ज्ञापन संख्या 523 दिनांक 15.02.2016 में निहित अवार्ड / डिक्री को रद्द करने और रद्द करने का जोरदार विरोध किया। जिसके तहत याचिकाकर्ता को 14,82,917/- रुपये की बकाया मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

17.05.2013 से अंतिम भुगतान तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक ब्याज दर के तीन गुना के साथ 14,82,917/- रुपये और प्रस्तुत करता है कि रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत याचिकाकर्ता के लिए एक प्रभावी, वैकल्पिक वैधानिक उपाय उपलब्ध है, और इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता की धारा 34 के तहत उपयुक्त अदालत में जाने का उपाय प्राप्त किया था (ग) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अंतर्गत डिक्री के रूप में 75% राशि जमा करनी चाहिए थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह रिट याचिका, बिना किसी योग्यता के होने के कारण, खारिज कर दी जाए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, जहां तक रिट याचिका की विचारणीयता के संबंध में प्रतिवादी के तर्क का संबंध है, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है जैसा कि व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क रजिस्ट्रार, मुंबई और अन्य (1998) 8 एस.सी.सी. -1 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया **है,**

जो इस निर्णय के पैराग्राफ 15 में निम्नानुसार पढाता है -

> *"15. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय के पास मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक रिट याचिका पर विचार करने या न करने का विवेक है। लेकिन उच्च न्यायालय ने अपने ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से एक यह है कि यदि कोई प्रभावी और प्रभावोत्पादक उपाय उपलब्ध है, तो उच्च न्यायालय सामान्य रूप से अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन इस न्यायालय द्वारा कम से कम तीन आकस्मिकताओं में एक बार के रूप में काम नहीं करने के लिए वैकल्पिक उपाय लगातार माना गया है, अर्थात्, जहां किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है या जहां प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है या जहां आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से*

<u>अधिकार क्षेत्र के बिना है या किसी अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी</u> गई है. इस बिंदु पर केस-लॉ की अधिकता है, लेकिन फोरेंसिक भँवर के इस चक्र को काटने के लिए, हम संवैधानिक कानून के विकासवादी युग के कुछ पुराने फैसलों पर भरोसा करेंगे क्योंकि वे अभी भी मैदान में हैं।"

परिषद द्वारा जारी नोटिसों को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक उपाय, क्योंकि परिषद द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की जाती है, या तो एमएसएमईडी अधिनियम के तहत, या मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत। इस मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारा विचार है कि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और निजी प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क कि याचिकाकर्ता के लिए वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष आक्षेपित अवार्ड को चुनौती देना खुला था, हालांकि ऐसा उपाय उपलब्ध है, लेकिन यह इस अर्थ में प्रभावी और प्रभावी नहीं था कि वाणिज्यिक न्यायालय नियमों के को नहीं देख सकता था।

8. इसके अतिरिक्त, **कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लि बनाम आयकर अधिकारी, कम्पनी जिला-I, कलकत्ता के मामले में** एआईआर 1961 एससी 372 **में यह** निर्णय दिया गया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पर विचार करने में न्यायालय, वैकल्पिक वैधानिक उपायों के बावजूद, प्रभावित नहीं होता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां प्राधिकारी जिसके खिलाफ रिट दायर की गई है, को बिना किसी कानूनी आधार के अधिकार क्षेत्र में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिखाया गया है या उसने अधिकार क्षेत्र को हड़पने का इरादा किया है।

9. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, जैसा कि पुरस्कार/डिक्री को सुविधा परिषद के गठन की योग्यता के आधार पर चुनौती दी गई है, जो *एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 21 के* अधिकारातीत है,इस न्यायालय का विचार है कि

यह ऐसा मामला नहीं है जहां रिट याचिका को छोड़ा नहीं जा सकता कि

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का आधार है क्योंकि याचिकाकर्ता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत सुविधा परिषद के गठन को चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

10. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, प्रतिवादी नंबर 4 का दावा निर्विवाद रूप से उस अवधि से संबंधित है जिसके पहले इसे एमएसएमई के रूप में पंजीकृत किया गया था। गुजरात राज्य सिविल सप्लाई कारपोरशन लिमिटेड बनाम माहाकाली फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 02) और अन्य (सु प्रा)नागरिक आपूत के मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए

(ख) मैसर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम

इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि सुविधा परिषद के पास उत्तरदाता नंबर 4 के दावे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

एमएसएमई के रूप में पंजीकृत किया गया था क्योंकि इसके पंजीकरण और परिणामी अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग इसके पंजीकरण से पहले की अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है, जिस समय के दौरान प्रतिवादी नंबर 4 सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार नहीं था; क्योंकि उस समय तक यह एमएसएमई के रूप में पंजीकृत नहीं था।

11. ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि आक्षेपित अधिनिर्णय/डिक्री एक परिषद द्वारा अधिकार क्षेत्र और सक्षमता के बिना पारित की गई थी, जिसका संविधान *एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 21 के* अधिकारातीत है क्योंकि इसमें 7 सदस्य हैं, जो

उक्त धारा 21 द्वारा उक्त परिषद लिए निर्धारित सदस्यों की अधिकता है , यह न्यायालय का यह सुविचारित विचार है कि इसे जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद संख्या 2015 का जेएचएमएसईएफसी 01, में पारित मेमो नंबर 523 दिनांक 15.02.2016 में निहित आक्षेपित अधिनिर्णय/डिक्री को रद्द कर दिया गया है। जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई थी, को रद्द कर दिया जाए और ख़ारिज किया जाए।

12. तदनुसार, उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा वाद संख्या जेएचएमएसईएफसी 01/2015, में पारित ज्ञापन संख्या 523 दिनांक 15.02.2016 में निहित आक्षेपित अधिनिर्णय/डिक्री को, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना की गई थी, को रद्द और खारिच किया जाता है

13. परिणामस्वरूप, इस रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च
न्यायालय, रांची
दिनांक 16 अप्रैल,

2024
एएफआर/अनिमेश-
सरोज

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।